recently commissioned. As a result, there will be an annual foreign exchange saving of the order of about Rs. 37 crores, when the plant will reach the full production capacity. The State Government has also taken care to ensure development of cottage and small scale industries along with the growth of the large and medium industries.

10. The State Government has also paid considerable attention to the drinking water needs of the people. During the Fourth Plan period, 40 more towns are expected to be covered with water supply facilities. The State Government has also given top priority to provide potable water supply facilities to "No source" villages. During the Fourth Five Year Plan period, it is expected to cover 1,000 villages with drinking water supply.

11. At the end, I would like to refer to the overall Fourth Plan performance of the State. Despite the stresses and strains on the State's economy, the severe drain on the State's financial resources and the great burden on administrative machinery which had to meet the challenges of unprecedented natural calamities which visited the State, the Fourth Plan is expected to end with a good record of performance, both in terms of financial and physical achievements. Against the approved Fourth Plan outlay of Rs. 455 crores, the actual expenditure is likely to exceed Rs. 540 crores. Significant over-reaches are likely to be registered under the important sectors such as irrigation, power, industries, roads including road transport, water supply and welfare of backward classes.

12.39½ hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1973-74

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the State of Gujarat for the year 1973-74.

12.40 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

DISSOLUTION OF GUJARAT ASSEMBLY

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक लोक महत्व के प्रोप्रीजरल तथा कांस्टीटयूशनल प्रोप्राइटी के सम्बन्ध में नियम 377 के अन्तर्गत चर्चा उठाना चाहता हूं जो गुजरात असैम्बली भंग किए जाने से सम्बन्धित है। मुझे आशा है कि आप सरकार से इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दिलवाने की कृपा करेंगे और वह पूरे फैक्ट्स सहित होगी। इस सम्बन्ध में मैं तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं। पहला यह है कि क्या प्रेजीडेंट ने असेम्बली को डिसाल्व करने के लिए नोटिफाई किया था, यदि हां, तो कितने बजे ? मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि डिसाल्यूशन डिक्लेरेशन के आठ घण्टे बाद क्या राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? तीसरा मुद्दा यह है कि बेरिएशन आफ दी फौर्मर प्रोक्लेमेशन आफ दी प्रेजीडेंट आर्टिकल 356 (2) के अनुसार बेरिएशन के लिए सबसिक्वेंट प्रोक्लेमेशन होना चाहिए था ? वह क्यों नहीं किया गया ?

सरकार का जो यह कृत्य है इससे स्पष्ट लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अपमान किया गया है। प्रधान मंत्री महोदय ने गुजरात असैम्बली के भंग होने से दो दिन पहले यह कहा था कि फासिस्ट तरीकों के आगे नहीं झुका जाएगा और जब तक गुजरात में सामान्य स्थिति कायम नहीं हो जाती है तब तक वहां पर किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए केन्द्रीय सरकार तैयार नहीं

[श्री फूलचन्द वर्मा]

है और न ही वहां की विधान सभा को भंग किया जाएगा।

जब मैंने सुबह अखबारों में यह पढ़ा कि गुजरात असेम्बली को भंग कर दिया गया तो इसको पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा स्वयं नहीं की, न गृह मंत्री ने कराई और न ही इस सदन के अन्दर इसकी घोषणा की गई। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अपमान पहले भी महामहिम राष्ट्रपति जी का नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे।

एक बात और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। मैं कह चुका हूं इससे पूर्व राष्ट्रपति महोदय का ऐसा अपमान नहीं किया गया था। प्रेस वालों को यह कहा गया था कि राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपाल को इस के बारे में नोटिफाई किया था लेकिन सच बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय को सुबह इनका पता लगा कि गुजरात असेम्बली को भंग कर दिया गया है। यह भी कहा गया था कि प्रधान मंत्री जब इस मूड में आई कि असेम्बली को भंग किया जाए उस समय राष्ट्रपति महोदय सो रहे थे यह कहा जा रहा है। इस पर मुझे आश्चर्य होता है। कोई जवान राष्ट्रपति महोदय होते तो मैं समझ सकता था कि वह जल्दी सो जाते हैं लेकिन ये तो बूढ़े राष्ट्रपति हैं और इनको डेढ़ बजे तक नींद नहीं आती है और जागते रहते हैं। उनकी स्वीकृति तो बड़ी आसानी से ली जा सकती थी। मैं चाहता हूं कि सरकार एक स्टेटमेंट दे जिस में फुल फैक्ट्स हों।

12.43 hrs.

GENERAL BUDGET, 1974-75—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

MR. SPEAKER: The House will now resume the discussion on the General Budget. Shri Sanjeevi Rao.

SHRI M. S. SANJEEVI RAO (Kakinada): I congratulate the Finance Minister for presenting such a bold Budget at a time when the country is passing through an acute economic crisis. As a matter of fact, taxation has not gone up to any remarkable degree nor had the deficit financing reached dizzy heights.

The role of coal as a source of commercial energy has been emphasised in the wake of shortage of oil resulting in the energy crisis. I congratulate the Finance Minister for allotting nearly Rs. 97 crores—a four-fold increase as compared to last year—for increasing the production of coal from 80 m. tonnes to 95 m. tonnes. One of the significant features is that he has allotted Rs. 1 crore for establishing a low-temperature carbonisation plant at the pit head of Singerreni colleries.

I hope that they will establish more low temperature carbonisation and gassification plants for converting coal into gas and transferring it to big cities for use as domestic fuel as well as for fuel for ovens and furnaces as well as for generating power.

But it is unfortunate that he has not given similar importance to electrical power generation. He should remember that electrical power is the real infrastructure for both industry and agriculture. As a matter of fact, industrialisation is a by product of electrical generation. In spite of the categorical announcement last year that they are going to